गन्ना क्षेत्र के लिए 5,500 करोड़ का पैकेज

केंद्र सरकार की तीन महीने के भीतर चीनी उद्योग के लिए दूसरी बार आर्थिक मदद की घोषणा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। गन्ना किसानों के बकाया राशि का जल्द भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को 5,500 करोड़ रुपये का पैकेज देने का फैसला किया। तीन महीने के भीतर ही केंद्र सरकार की तरफ से चीनी उद्योग को यह दूसरा आर्थिक पैकेज दिया गया है।

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इससे पहले जून में चीनी उद्योग के लिए 8,500 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा की गई थी। इससे पहले यूपी सरकार ने मंगलवार को गन्ना किसानों को भुगतान के लिए निजी मिलों को 4 हजार करोड़ का लोन देने की घोषणा की है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि किसानों के उत्पादन सहायता को दोगुना से अधिक करने तथा चीनी का निर्यात करने वाली मिलों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए कुल मिलाकर 5,500 करोड़ रुपये का पैकेज देने का फैसला किया गया है। इस आशय का प्रस्ताव खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दिया था। यह राशि चीनी मिलों को दी जाएगी ताकि उनकी नकदी की स्थिति में सुधार हो। उन्होंने बताया कि गन्ने की लागत की भरपायी करने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 13.88 रुपये की दर से कुल 4,163 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। चीनी निर्यात को सुगम बनाने के लिए आंतरिक ढुलाई एवं अन्य प्रभार संबंधी खर्चों पर 1,375 करोड़ रुपये की परिवहन सब्सिडी दी जाएगी।

10%

तक गिरे चीनी कंपनियों के शेयर बुधवार को पैकेज मंजूरी के बावजूद

8,500 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा की गई थी जून में

12,959 करोड़ रुपये बकाया : खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश भर में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया 12,959 करोड़ रुपये है। इसी साल मई के अंतिम सप्ताह में तो यह 23,232 करोड़ रुपये के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष 20 लाख टन के मुकाबले इस साल निर्यात का लक्ष्य बढ़ा कर 50 लाख टन कर दिया गया है।

किसानों की मदद के लिए फैसला

केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इस साल करीब 350 लाख टन चीनी का अनुमान है जबकि खपत 250 लाख टन का ही है। पिछले साल के अधिशेष के रूप में 39 लाख टन का स्टॉक मिलों के पास है। अगले साल करीब 165 लाख टन चीनी का अधिशेष होगा। इसलिए ही गन्ना किसानों को दी जाने वाली प्रति क्विंटल सहायता की राशि को 5.50 रुपये से बढ़ा कर 13.88 रुपये कर दी गई है। निर्यात के लिए लक्ष्य को बढ़ा कर परिवहन सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।

Amar Ujala
27-09-18.